

भारत सरकार  
शिक्षा मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या-1242  
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

एक राष्ट्र-एक शिक्षा परिषद

1242. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) क्या सरकार पूरे देश में 'एक राष्ट्र- एक शिक्षा परिषद' और 'एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम' लागू करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार द्वारा उक्त विषय पर इसकी आवश्यकता, व्यवहार्यता और संभावित लाभों का आकलन करने के लिए कोई सर्वेक्षण, विशेषज्ञ विचार-वमर्श, सेमिनार और कार्यशाला आयोजित की गई है या अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है और यदि हां, तो ऐसे सर्वेक्षण या चर्चाओं के प्रमुख निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) इस प्रस्ताव के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शाने वाले या सहयोग करने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के नाम क्या हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ग) शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय है। जिन स्कूलों का स्वामित्व/वत्त पोषण केंद्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, उन स्कूलों के प्रबंधन से जुड़े मामलों को संबंधित राज्य सरकार के नियमों और अनुदेशों के अनुसार विनियमित किया जाता है। इसके अलावा, राज्य बोर्डों के तहत स्कूलों के लिए पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें तैयार करना संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। इस प्रकार, एक राष्ट्र-एक शिक्षा बोर्ड अथवा एक समान राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसरण में, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) की स्थापना 8 फरवरी, 2023 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) के तहत की गई थी। यह स्कूल मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मानक-निर्धारण निकाय के रूप में

कार्य करता है और मूल्यांकन सुधारों के संबंध में बोर्डों का मार्गदर्शन करता है, राज्य उपलब्धि सर्वेक्षणों में सहयोग करता है और राष्ट्रीय स्तर पर अधगम परिणामों को श्रेष्ठ बनाने हेतु राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (अब परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण) आयोजित करता है।

राज्य की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को स्वीकार करते हुए देशभर में छात्रों की गतिशीलता और शैक्षणिक प्रदर्शन में समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत में सभी मान्यताप्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए, शिक्षा के पांच प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बुनियादी ढांचा और समावेशिता में मानकों को सुसंगत बनाने के लिए वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र- परख, एनसीईआरटी द्वारा 'बोर्डों की समानता' में एक व्यापक अध्ययन शुरू किया गया था; स्कूल शिक्षा बोर्डों के साथ गहन परामर्श के आधार पर इस कार्य के मुख्य निष्कर्षों और नीतिगत सिफारिशों को [https://ncert.nic.in/parakh/pdf/Equivalence\\_of\\_Boards\\_Report.pdf](https://ncert.nic.in/parakh/pdf/Equivalence_of_Boards_Report.pdf) पर देखा जा सकता है।

शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित 'अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024' और दिनांक 2 जुलाई, 2025 को आयोजित "बोर्डों के पाठ्यक्रम और मूल्यांकन समतुल्यता संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन" के दौरान रिपोर्ट के प्रमुख सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और एनसीईआरटी के सचिवों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, प्रश्नपत्र टेम्पलेटों के मानकीकरण को बढ़ावा देने और मूल्यांकन में श्रेष्ठ कार्यप्रथाओं को अपनाने के लिए राज्य शिक्षा बोर्डों के साथ परख, एनसीईआरटी द्वारा कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

\*\*\*\*\*